Var-14669

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

विवाचको प्राप्त ।

बमारी जन्म विवर्ष एक

MRA का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड ३ — उप-खण्ड (iii) PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY PO-140

KM- 05

115 परा

किया

सं. 121] No. 121] नई दिल्ली, बृहस्पतिबार, जून 10, 2004/ज्येन्ड 20, 1926 NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 10, 2004/JYAISTHA 20, 1926

प्रभारी <u>रा० वि० ए</u>क्स

भारत निर्धाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2004

आ.अ. 162(अ).— यतः, भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी और भारत के राजपत्र असाधारण में 4 जून, 2004 को प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा की है कि उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में राज्यों के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में राज्य सभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें।

सास्यी

×	राज्य	निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या
	(1)	(2)
1.	छत्तीसग ढ़	2
2.	मध्य प्रदेश	3
3.	तमिलनाडु	6
4.:	उड़ीसा	3
5.	महाराष्ट्र	6
6.	पंजाब	2
Ź	राजस्थान	4
8.	उत्तर प्रदेश	- 11
9.	उत्तरांचल	1 .
10.	बिहार	5
11.	झारखण्ड	2 .
12.	हरियाणा	2

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा 4 जून, 2004 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित तारीख 4 जून, 2004 की अपनी अधिसूचना सं0 318/2/2004 (1) के द्वारा :--

(क)नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख –	11 जून , 2004 (शुक्रवार)
(ख)नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख -	12 जून , 2004 (शनिवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख	14 जून , 2004 (सोमवार)
(घ)वह तारीख , जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, और	21 जून , 2004 (सोमवार)
(इ)वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा	23 जून , 2004 (बुधवार)
नियत किया था: और	

और यतः, माननीय उच्चतम न्यायालय ने डबल्यू पी. (सी.) 2004 का 217 पर तारीख 4 जून, 2004 के अपने अन्तरिम आदेश द्वारा अगले आदेशों तक अधिसूचना पर रोक लगा दी थी और इसके साथ—'साथ माननीय न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को एक पार्टी के रूप में अपने अन्तरिम आदेश में संशोधन के लिए न्यायालय के समक्ष जाने की अनुमित दे दी है;

और यतः, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना पर 4 जून, 2004 के आदेश के द्वारा अधिसूचना पर लगायी गई रोक के मददे नजर , निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग आफिसरों को यह अनुदेश दिए थे कि अगले आदेश होने तक वे नामनिर्देशन पत्र स्वीाकार न करें;

और यत:, निर्वाचन आयोग ने 5.6.2004 को उच्चतम न्यायालय के समक्ष डबल्यू पी. (सी.) 217/2004 में आई. ए. सं0 3 के तहत 4.6.2004 को लगाई गई रोक हटाने के लिए एक आवेदन दाखिल किया था और राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने का अनुरोध किया ;

और यतः, उच्चतम न्यायालय ने 9 जून, 2004 के अपने आदेश द्वारा रोक को खारिज करते हुए आई. ए. सं0 3 का निपटान कर दिया और यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन कायकम में संशोधन करने की अनुमित देते हुए निर्वाचन जारी रखने की अनुमित दे दी है ;

और अब, उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित 9.6.2004 के उक्त आदेश के अनुसार और संविधान के अनुच्छेद 324 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 153 द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए और साधारण खण्ड अधिनियम 1897(1897 का 10) की धारा 21 और इस ओर से इसे सक्षम बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों द्वारा यह निदेश देता है कि दिनांक 4 जून, 2004 को राष्ट्रपत्तीय अधिसूचना द्वारा जारी निर्वाचन प्रकिया पुनः शुरू की जाए और कि 4 जून, 2004 की आयोग की अधिसूचना निम्न प्रकार से संशोधित की जाएगी;

खण्ड (क), (ख), (ग), (घ)और (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगें :

(क)नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख –	17 जून , 2004 (बृहस्पतिवार)
(ख)नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख –	18 जून , 2004 (शुक्रवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख—	21 जून , 2004 (सोमवार)
(घ)वह तारीख , जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, –	28 जून , 2004 (सोमवार)
(ड़)वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	30 जून , 2004 (बुधवार)
	r_1 1.

[सं. 318/2/2004(1)] आदेश से, ए.के. मजुमदार, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2004

O.N. 162(E).— Whereas, the President of India has by notification under Section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) published in the Gazette of India, Extraordinary dated 4th June 2004 been pleased to call upon the elected members of Legislative Assemblies of the States, specified in column (1) of the TABLE below, to elect to the Council of States, the number of members specified against that State in column (2) of the said TABLE:

TABLE

STATE	NO. OF MEMBERS TO BE ELECTED
(1)	(2)
1. Chhattisgarh	2
2. Madhya Pradesh	3
3. Tamil Nadu	6
4. Orissa	3
5. Maharashtra	6
6. Punjab	2
7. Rajasthan	4
8. Uttar Pradesh	11-
9. Uttaranchal	1
10. Bihar	5
11. Jharkhand	2
12. Haryana	2

Whereas, in pursuance of the provisions of Sub-section (1) of Section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission vide its Notification No. 318/2/2004 (1) stated 4th June 2004 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 4th June 2004, had appointed -

- (a) the 11th June, 2004 (Friday), as the last date for making nominations;
- (b) the 12th June, 2004 (Saturday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- (c) the 14th June, 2004 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 21st June, 2004 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 23rd June, 2004 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court by its interim order dated 4th June 2004 on W.P. (C) No. 217 of 2004, was pleased to stay the Notification until further orders and while adding the Election Commission as a party permitted it to move the Hon'ble Court for modification of its interim order;

And whereas, pursuant to the order dated 4th June 2004 of the Hon'ble Supreme Court staying the Notification, the Election Commission had instructed the Returning Officers not to accept nomination papers till further orders;

And whereas, the Election Commission on 5.6.2004 filed an application being I.A. No. 3 in W.P. (C) 217/2004, before the Hon'ble Supreme Court seeking vacation of the stay granted on 4.6.2004 and prayed that the biennial elections to the Rajya Sabha be completed as per schedule;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court in its order dated 9th June 2004 was pleased to dispose of I.A. No. 3 by vacating the stay and permitting the Election Commission to revise the election schedule, if necessary, and proceed with the election;

Now, therefore, the Election Commission pursuant to the above order dated 9.6.2004 passed by the Hon'ble Supreme Court and in exercise of the powers conferred on it by Article 324 of the Constitution of India, read with sub-section (1) of Section 39 and 153 of the Representation of the People Act, 1951, Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and all other powers enabling it in this behalf hereby directs that the election process set in motion by the Presidential Notification dated 4th June 2004 shall be resumed and that Election Commission Notification dated 4th June 2004 shall be amended as follows:

For clauses (a), (b), (c), (d) and (e), the following clauses shall be substituted:

- (a) the 17th June, 2004 (Thursday), as the last date for making nominations;
- (b) the 18th June, 2004 (Friday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- (c) the 21st June, 2004 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 28th June, 2004 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 30th June, 2004 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed;

[No. 318/2/2004(1)] By Order, A. K. MAJUMDAR, Secy.

अधिसूचना नई दिल्ली, 10 जून, 2004

आ.अ. 163(अ).— यतः, भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी और भारत के राजपत्र, असाधारण में 4 जून, 2004 को प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्म (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा की है कि उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में राज्यों के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में राज्य सभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें।

सारणी

राज्य		निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या	
	(1)	(2)	
1.	आन्ध्र प्रदेश	6	
2.	कर्नाटक	4	

यतः, लोकं प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की, धारा 39 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा 4 जून, 2004 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित तारीख 4 जून, 2004 की अपनी अधिसूचना सं0 318/2/2004 (2) के द्वारा :-

(क)नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख —	11 जून , 2004	(शुकवार)
(ख)नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख -	12 जून , 2004	(शनिवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख-	14 जून , 2004	(सोमवार)
(घ)वह तारीख , जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, और	21 जून , 2004	(सोमवार)
(इ)वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा	23 जून , 2004	(बुधवार)
नियत किया था और		

और यतः, माननीय उच्चतम न्यायालय ने डबल्यू पी. (सी.) 2004 का 217 पर तारीख 4 जून, 2004 के अपने अन्तरिम आदेश द्वारा अगले आदेशों तक अधिसूचना पर रोक लगा दी थी और इसके साथ—साथ माननीय न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को एक पार्टी के रूप में अपने अन्तरिम आदेश में संशोधन के लिए न्यायालय के समक्ष जाने की अनुमित दे दी है;

और यतः, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना पर 4 जून, 2004 के आदेश के द्वारा अधिसूचना पर लगायी गई रोक के मददे नजर , निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग आफिसरों को यह अनुदेश दिए थे कि अगले आदेश होने तक वे नामनिर्देशन पत्र स्वीकार न करें ;

और यतः, निर्वाचन आयोग ने 5.6.2004 को उच्चतम न्यायालय के समक्ष डबल्यू पी. (सी.) 217/2004 में आई. ए. सं0 3 के तहत 4.6.2004 को लगाई गई रोक हटाने के लिए एक आवेदन दाखिल किया था और राज्य समा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन कार्यकम के अनुसार पूरा करने का अनुरोध किया ;

और यतः, उच्चतम न्यायालय ने 9 जून, 2004 के अपने आदेश द्वारा रोक को खारिज करते हुए आई. ए. सं0 3 का निपटान कर दिया और यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन कार्यक्रम में संशोधन करने की अनुमित देते हुए निर्वाचन जारी रखने की अनुमित दे दी है ;

अतः अब, उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित 9.6.2004 के उक्त आदेश के अनुसार और संविधान के अनुच्छेद 324 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 153 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और साधारण खण्ड अधिनियम 1897(1897 का 10) की धारा 21 और इस ओर से इसे सक्षम बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों द्वारा यह निदेश देता है कि दिनांक 4 जून, 2004 को राष्ट्रपत्तीय अधिसूचना द्वारा जारी निर्वाचन प्रकिया पुनः शुरू की जाए और 4 जून, 2004 की आयोग की अधिसूचना निम्न प्रकार से संशोधित की जाएगी;

180165/04

		0 00	0 0 0	
खण्ड (क) (ख) (ग), (घ) और (ड.) के स्थान	पर निम्नलिखित खण्ड	प्रतिस्थापित वि	ए जाएग :

(क)नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख –	17 जून , 2004 (बृहस्पतिवार)
(खं)नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख	18 जून , 2004 (शुकवार)

[सं. 318/2/2004(2)] आदेश से,

ए.के. मजुमदार, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2004

O.N. 163(E).—Whereas, the President of India has by Notification under Section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) published in the Gazette of India, Extraordinary dated 4th June 2004 been pleased to call upon the elected members of Legislative Assemblies of the States, specified in column (1) of the **TABLE** below, to elect to the Council of States, the number of members specified against that State in column (2) of the said TABLE;

TABLE

STATE	NO. OF MEMBERS TO BE ELECTED
(1)	(2)
1. Andhra Pradesh	6
2. Karnataka	4

Whereas, in pursuance of the provisions of Sub-section (1) of Section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission vide its Notification No. 318/2/2004 (2) dated 4th June 2004 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 4th June 2004, had appointed -

- (a) the 11th June, 2004 (Friday), as the last date for making nominations;
- (b) the 12th June, 2004 (Saturday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- (c) the 14th June, 2004 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 21st June, 2004 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 23rd June, 2004 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court by its interim order dated 4th June 2004 on W.P. (C) No. 217 of 2004, was pleased to stay the Notification until further orders and while adding the Election Commission as a party permitted it to move the Hon'ble Court for modification of its interim order;

And whereas, pursuant to the order dated 4th June 2004 of the Hon'ble Supreme Court staying the Notification, the Election Commission had instructed the Returning Officers not to accept nomination papers till further orders;

And whereas, the Election Commission on 5.6.2004 filed an application being I.A. No. 3 in W.P. (C) 217/2004, before the Hon'ble Supreme Court seeking vacation of the stay granted on 4.6.2004 and prayed that the biennial elections to the Rajya Sabha be completed as per schedule;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court in its order dated 9th June 2004 was pleased to dispose of I.A. No. 3 by vacating the stay and permitting the Election Commission to revise the election schedule, if necessary, and proceed with the election;

Now, therefore, the Election Commission pursuant to the above order dated 9.6.2004 passed by the Hon'ble Supreme Court and in exercise of the powers conferred on it by Article 324 of the Constitution of India, read with sub-section (1) of Section 39 and 153 of the Representation of the People Act, 1951, Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and all other powers enabling it in this behalf hereby directs that the election process set in motion by the Presidential Notification dated 4th June 2004 shall be resumed and that Election Commission Notification dated 4th June 2004 shall be amended as follows:

For clauses (a), (b), (c), (d) and (e), the following clauses shall be substituted:

- (a) the 17th June, 2004 (Thursday), as the last date for making nominations;
- (b) the 18th June, 2004 (Friday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- (c) the 21st June, 2004 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 28th June, 2004 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 30th June, 2004 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed;

[No. 318/2/2004(2)] By Order, A. K. MAJUMDAR, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2004

आ.अ. 164(अ).—यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 147 और धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग ने, 4 जून, 2004 को भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित अपनी तारीख 4 जून, 2004 की अधिसूचना सं0 100/रा0भा0—आ0प्र0/1/2003 (1) द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा की थी कि वे श्री के. एम. खान की मृत्यु हो जाने के कारण राज्य सभा में उस स्थान को भरने के लिए एक सदस्य निर्वाचित

कर दें :

(क)नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख –	11 जून , 2004	(शुकवार)
(ख)नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख –	12 जून , 2004	(शनिवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख-	14 जून , 2004	(सोमवार)
(घ)वह तारीख , जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, और	21 जून , 2004	(सोमवार)
(ड़)वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा	23 जून , 2004	(बुधवार)
नियत किया था; और		

और यतः, माननीय उच्चतम न्यायालय ने डबल्यू पी. (सी.) सं० 2004 का 217 पर तारीख 4 जून, 2004 के अपने अन्तरिम आदेश द्वारा अगले आदेशों तक अधिसूचना पर रोक लगा दी थी और इसके साथ—'साथ माननीय न्यायालय ने अपने अन्तरिम आदेश में संशोधन के लिए निर्वाचन आयोग को एक पार्टी के रूप में न्यायालय के समक्ष जाने की अनुमति दे दी है;

और यतः, माननीय उच्चतम न्यायायल ने 4 जून, 2004 के आदेश के द्वारा अधिसूचना पर लगायी गई रोक के मददे नजर, निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग आफिसरों को यह अनुदेश दिए थे कि अगले आदेश होने तक वे नामनिर्देशन पत्र स्वीकार न करें ;

और यतः, निर्वाचन आयोग ने को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष डबल्यू पी. (सी.) 217/2004 में आई. ए. सं0 3 के तहत 4.6.2004 को लगाई गई रोक हटाने के लिए 5.6.2004 एक आवेदन दाखिल किया था और राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने का अनुरोध किया था ;

और यतः, माननीय उच्चतम न्यायालय ने 9 जून, 2004 के अपने आदेश द्वारा रोक को खारिज करते हुए आई. ए. सं0 3 का निपटान कर दिया और यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन आयोग को निर्वाचन कार्यक्रम में संशोधन करने की अनुमति देते हुए निर्वाचन जारी रखने की अनुमति दे दी है ;

और अब, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित 9.6.2004 के उक्त आदेश के अनुसार और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 153 के साथ पठित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए और साधारण खण्ड अधिनियम 1897(1897 का 10) की धारा 21 और इसकी ओर से इसे सक्षम बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों द्वारा यह निदेश देता है कि निर्वाचन प्रक्रिया पुनः शुरू की जाए और कि 4 जून, 2004 की निर्वाचन आयोग की अधिसूचना निम्न प्रकार से संशोधित की जाएगी ;

खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ.) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगें :

(क)नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख —	17 जून , 2004 (बृहस्पतिवार)
(ख)नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीखं –	18 जून , 2004 (शुक्रवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख-	21 जून , 2004 (सोमवार)
(घ)वह तारीख , जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, –	28 जून , 2004 (सोमवार)
(इ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	30 जून , 2004 (बुधवार)

[सं. 100/रा.स.–आ.प्र./1/2003(1)] आदेश से, ए.के. मजुमदार, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2004

O.N. 164(E).— Whereas, in pursuance of section 147, sub-section (1) of section 39 and section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India vide its Notification No. 100/CS-AP/1/2003 (1) dated 4th June 2004 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 4th June 2004, pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Andhra Pradesh to elect a person to fill the seat in the Council of States, caused by the death of Shri K.M. Khan, had appointed:

- (a) the 11th June, 2004 (Friday), as the last date for making nominations;
- (b) the 12th June, 2004 (Saturday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- (c) the 14th June, 2004 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 21st June, 2004 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 23rd June, 2004 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court by its interim order dated 4th June 2004 on W.P. (C) No. 217 of 2004, was pleased to stay the Notification until further orders and while adding the Election Commission as a party permitted it to move the Hon'ble Court for modification of its interim order;

And whereas, pursuant to the order dated 4th June 2004 of the Hon'ble Supreme Court staying the Notification, the Election Commission had instructed the Returning Officers not to accept nomination papers till further orders;

And whereas, the Election Commission on 5.6.2004 filed an application being I.A. No. 3 in W.P. (C) 217/2004, before the Hon'ble Supreme Court seeking vacation of the stay granted on 4.6.2004 and prayed that the biennial elections to the Rajya Sabha be completed as per schedule;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court in its order dated 9th June 2004 was pleased to dispose of I.A. No. 3 by vacating the stay and permitting the Election Commission to revise the election schedule, if necessary, and proceed with the election;

Now, therefore, the Election Commission pursuant to the above order dated 9.6.2004 passed by the Hon'ble Supreme Court and in exercise of the powers conferred on it by Article 324 of the Constitution of India, read with sub-section (1) of Section 39 and 153 of the Representation of the People Act, 1951, Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and all other powers enabling it in this behalf hereby directs that the election process shall be resumed and that Election Commission Notification dated 4th June 2004 shall be amended as follows:

180191/04

For clauses (a), (b), (c), (d) and (e), the following clauses shall be substituted:

- (a) the 17th June, 2004 (Thursday), as the last date for making nominations;
- (b) the 18th June, 2004 (Friday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- (c) the 21st June, 2004 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 28th June, 2004 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 30th June, 2004 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed;

[No. 100/CS-AP/1/2003(1)] By Order, A. K. MAJUMDAR, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2004

आ.अ. 165(अ).—यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 147 और धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग ने, 4 जून, 2004 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अपनी तारीख 4 जून, 2004 की अधिसूचना सं0 100/रा०स0—बि0/1/2004(1) द्वारा बिहार राज्य के विधानसमा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा की थी कि वे लोक सभा के लिए श्री राजीव रंजन के निर्वाचित हो जाने के कारण राज्य सभा में रिक्त हुए स्थान को भरने के लिए एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें;

(क)नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख –	11 जून , 2004	, ,
(ख)नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख –	12 जून , 2004	(शनिवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख-	14 जून , 2004	(सोमवार)
(घ)वह तारीख , जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, और	21 जून , 2004	(सोमवार)
(इ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा	23 जून , 2004	(बुधवार)
नियत किया था; और		

और यतः, माननीय उच्चतम न्यायालय ने डबल्यू पी. (सी.) सं० 2004 का 217 पर तारीख 4 जून, 2004 के अपने अन्तरिम आदेश द्वारा अगले आदेशों तक अधिसूचना पर रोक लगा दी थी और इसके साथ—'साथ माननीय न्यायालय ने अपने अन्तरिम आदेश में ,संशोधन के लिए निर्वाचन आयोग को एक पार्टी के रूप में न्यायालय के समक्ष जाने की अनुमित दे दी है ;

और यतः, माननीय उच्चतम न्यायायल ने 4 जून, 2004 के आदेश के द्वारा अधिसूचना पर लगायी गई रोक के मददे नजर, निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग आफिसरों को यह अनुदेश दिए थे कि अगले आदेश होने तक वे नामनिर्देशन पत्र स्वीकार न करें;

और यतः, निर्वाचन आयोग ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष डबल्यू पी. (सी.) 217/2004 में आई. ए. संठ 3 के तहत 4.6.2004 को लगाई गई रोक हटाने के लिए 5.6.2004 को एक आवेदन दाखिल किया था और राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन, कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने का अनुरोध किया था ;

और यतः, माननीय उच्चतम न्यायालय ने 9 जून, 2004 के अपने आदेश द्वारा रोक को खारिज करते हुए आई. ए. सं0 3 का निपटान कर दिया और यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन आयोग को निर्वाचन कार्यक्रम में संशोधन करने की अनुमति देते हुए निर्वाचन जारी रखने की अनुमति दे दी है ;

और अब, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित 9.6.2004 के उक्त आदेश के अनुसार और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 153 के साथ पठित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए और साधारण खण्ड अधिनियम 1897(1897 का 10) की धारा 21 और इसकी ओर से इसे सक्षम बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों द्वारा यह निदेश देता है कि निर्वाचन प्रकिया पुनः शुरू की जाए और कि 4 जून, 2004 की निर्वाचन आयोग की अधिसूचना निम्न प्रकार से संशोधित की जाएगी;

खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ.) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगें :

(क)नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख -	17 जून , 2004 (बृहस्पतिवार)
(ख)नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख –	18 जून , 2004 (शुक्रवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख—	21 जून , 2004 (सोमवार)
(घ)वह तारीख , जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, –	28 जून , 2004 (सोमवार)
(इ)वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	30 जून , 2004 (बुधवार)

[सं. 100/रा.स.-बि./1/2004(1)] आदेश से, ए.के. मजुमदार, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2004

O.N. 165(E).— Whereas, in pursuance of section 147, sub-section (1) of section 39 and section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India vide its Notification No. 100/CS-BR/1/2004 (1) dated 4th June 2004 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 4th June 2004, pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Bihar to elect a person to fill the seat in the Council of States, vacated by Shri Rajiv Ranjan Singh on his election to the House of the People, had appointed:-

- (a) the 11th June, 2004 (Friday), as the last date for making nominations;
- (b) the 12th June, 2004 (Saturday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- (c) the 14th June, 2004 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 21st June, 2004 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 23rd June, 2004 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court by its interim order dated 4th June 2004 on W.P. (C) No. 217 of 2004, was pleased to stay the Notification until further orders and while adding the Election Commission as a party permitted it to move the Hon'ble Court for modification of its interim order;

And whereas, pursuant to the order dated 4th June 2004 of the Hon'ble Supreme Court staying the Notification, the Election Commission had instructed the Returning Officers not to accept nomination papers till further orders;

And whereas, the Election Commission on 5.6.2004 filed an application being I.A. No. 3 in W.P. (C) 217/2004, before the Hon'ble Supreme Court seeking vacation of the stay granted on 4.6.2004 and prayed that the biennial elections to the Rajya Sabha be completed as per schedule;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court in its order dated 9th June 2004 was pleased to dispose of I.A. No. 3 by vacating the stay and permitting the Election Commission to revise the election schedule, if necessary, and proceed with the election;

Now, therefore, the Election Commission pursuant to the above order dated 9.6.2004 passed by the Hon'ble Supreme Court and in exercise of the powers conferred on it by Article 324 of the Constitution of India, read with sub-section (1) of Section 39 and 153 of the Representation of the People Act, 1951, Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and all other powers enabling it in this behalf hereby directs that the election process shall be resumed and that Election Commission Notification dated 4th June 2004 shall be amended as follows:

For clauses (a), (b), (c), (d) and (e), the following clauses shall be substituted:

- (a) the 17th June. 2004 (Thursday), as the last date for making nominations;
- (b) the 18th June, 2004 (Friday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- (c) the 21st June, 2004 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 28th June, 2004 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 30th June, 2004 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed;

[No. 100/CS-BR/1/2004(1)] By Order, A. K. MAJUMDAR, Secv.

(शनिवार)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुन, 2004

आ.अ. 166(अ).— यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 147 और धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग ने, 4 जून, 2004 को असाधारण में प्रकाशित अपनी तारीख 4 जून, 2004 की अधिसूचना सं0 के राजपत्र, 100/रा0स0-बि0/2/2004(1) द्वारा बिहार राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा की थी कि वे लोक सभा के लिए श्री लालू प्रसाद के निर्वाचित हो जाने के कारण राज्य सभा में रिक्त हुए स्थान को भरने के लिए एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें ;

(क)नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख -11 जून , 2004 (शुक्वार) (ख)नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख -12 जून , 2004

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख— (घ)वह तारीख , जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, और	14 जून , 2004 21 जून , 2004	
(इ)वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा	23 जून , 2004	
नियत किया था; और	•	

और यतः, माननीय उच्चतम न्यायालय ने डबल्यू पी. (सी.) सं० 2004 का 217 पर तारीख 4 जून, 2004 के अपने अन्तरिम आदेश द्वारा अगले आदेशों तक अधिसूचना पर रोक लगा दी थी और इसके साथ—'साथ माननीय न्यायालय ने अपने अन्तरिम आदेश में संशोधन के लिए निर्वाचन आयोग को एक पार्टी के रूप में न्यायालय के समक्ष जाने की अनुमति दे दी है;

और यतः, माननीय उच्चतम न्यायायल ने 4 जून, 2004 के आदेश के द्वारा अधिसूचना पर लगायी गई रोक के मददे नजर, निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग आफिसरों को यह अनुदेश दिए थे कि अगले आदेश होने तक वे नामनिर्देशन पत्र स्वीकार न करें;

और यतः, निर्वाचन आयोग ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष डबल्यू पी. (सी.) 217/2004 में आई. ए. संठ 3 के तहत 4.6.2004 को लगाई गई रोक हटाने के लिए 5.6.2004 को एक आवेदन दाखिल किया था और राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन, कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने का अनुरोध किया था ;

और यतः, माननीय उच्चतम न्यायालय ने 9 जून, 2004 के अपने आदेश द्वारा रोक को खारिज करते हुए आई. ए. सं0 3 का निपटान कर दिया और यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन आयोग को निर्वाचन कार्यक्रम में संशोधन करने की अनुमति देते हुए निर्वाचन जारी रखने की अनुमित दे दी है ;

और अब, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित 9.6.2004 के उक्त आदेश के अनुसार और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 153 के साथ पठित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए और साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (1897 का 10) की धारा 21 और इसकी ओर से इसे सक्षम बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों द्वारा यह निदेश देता है कि निर्वाचन प्रक्रिया पुनः शुरू की जाए और कि 4 जून, 2004 की निर्वाचन आयोग की अधिसूचना निम्न प्रकार से संशोधित की जाएगी;

खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ.) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगें :

(क)नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख <u>–</u>	17 जून , 2004 (बृहस्पतिवार)
(ख)नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख –	18 जून , 2004 (शुकवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख-	21 जून , 2004 (सोमवार)
(घ)वह तारीख , जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, —	28 जून , 2004 (सोमवार)
(ड)वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	30 जून , 2004 (बुधवार)

[सं. 100/रा.स.-बि./2/2004(1)] आदेश से, ए.के. मजुमदार, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2004

O.N. 166(E).— Whereas, in pursuance of section 147, sub-section (1) of section 39 and section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India vide its Notification No. 100/CS-BR/2/2004 (1) dated 4th June 2004 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 4th June 2004, pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Bihar to elect a person to fill the seat in the Council of States, vacated by Shri Lalu Prasad on his election to the House of the People, had appointed:-

- (a) the 11th June, 2004 (Friday), as the last date for making nominations:
- (b) the 12th June, 2004 (Saturday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- (c) the 14th June, 2004 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 21st June, 2004 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 23rd June, 2004 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court by its interim order dated 4th June 2004 on W.P. (C) No. 217 of 2004, was pleased to stay the Notification until further orders and while adding the Election Commission as a party permitted it to move the Hon'ble Court for modification of its interim order;

And whereas, pursuant to the order dated 4th June 2004 of the Hon'ble Supreme Court staying the Notification, the Election Commission had instructed the Returning Officers not to accept nomination papers till further orders;

And whereas, the Election Commission on 5.6.2004 filed an application being I.A. No. 3 in W.P. (C) 217/2004, before the Hon'ble Supreme Court seeking vacation of the stay granted on 4.6.2004 and prayed that the biennial elections to the Rajya Sabha be completed as per schedule;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court in its order dated 9th June 2004 was pleased to dispose of I.A. No. 3 by vacating the stay and permitting the Election Commission to revise the election schedule, if necessary, and proceed with the election;

Now, therefore, the Election Commission pursuant to the above order dated 9.6.2004 passed by the Hon'ble Supreme Court and in exercise of the powers conferred on it by Article 324 of the Constitution of India, read with sub-section (1) of Section 39 and 153 of the Representation of the People Act, 1951, Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and all other powers enabling it in this behalf hereby directs that the election process shall be resumed and that Election Commission Notification dated 4th June 2004 shall be amended as follows:

For clauses (a), (b), (c), (d) and (e), the following clauses shall be substituted:

- (a) the 17th June, 2004 (Thursday), as the last date for making nominations;
- (b) the 18th June, 2004 (Friday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- (c) the 21st June, 2004 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 28th June, 2004 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 30th June, 2004 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed;

[No. 100/CS-BR/2/2004(1)] By Order, A. K. MAJUMDAR, Secy.

ं आंधसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2004

आ.अ. 167(अ).— यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 147 और धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग ने, 4 जून, 2004 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अपनी तारीख 4 जून, 2004 की अधिसूचना सं0 100/रा0स0—म0प्र0/1/2004(1) द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा की थी कि वे राज्य सभा में उस स्थान को, जो लोक सभा के लिए श्री कैलाशचन्द्र के निर्वाचित हो जाने के कारण राज्य सभा में रिक्त हुए स्थान को भरने के लिए एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें;

(क)नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख –	11 जून , 2004	(शुकवार)
(ख)नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख –	12 जून , 2004	(शनिवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख	14 जून , 2004	(सोमवार)
(घ)वह तारीख , जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, और	21 जून , 2004	(सोमवार)
(ड़)वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा	23 जून , 2004	(बुधवार)
नियत किया था; और		

और यतः, माननीय उच्चतम न्यायालय ने डबल्यू पी. (सी.) सं० 2004 का 217 पर तारीख 4 जून, 2004 के अपने अन्तरिम आदेश द्वारा अगले आदेशों तक अधिसूचना पर रोक लगा दी थी और इसके साथ—'साथ माननीय न्यायालय ने अपने अन्तरिम आदेश में संशोधन के लिए निर्वाचन आयोग को एक पार्टी के रूप में न्यायालय के समक्ष जाने की अनुमित दे दी है ;

और यतः, माननीय उच्चतम न्यायायल ने 4 जून, 2004 के आदेश के द्वारा अधिसूचना पर लगायी गई रोक के मददे नजर, निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग आफिसरों को यह अनुदेश दिए थे कि अगले आदेश होने तक वे नामनिर्देशन पत्र स्वीकार न करें ;

और यतः, निर्वाचन आयोग ने को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष डबल्यू पी. (सी.) 217/2004 में आई. ए. संठ 3 के तहत 4.6.2004 को लगाई गई रोक हटाने के लिए 5.6.2004 एक आवेदन दाखिल किया था और राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन कार्यकम के अनुसार पूरा करने का अनुरोध किया था ;

और यतः, माननीय उच्चतम न्यायालय ने 9 जून, 2004 के अपने आदेश द्वारा रोक को खारिज करते हुए आई. ए. सं0 3 का निपटान कर दिया और यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन आयोग को निर्वाचन कार्यक्रम में संशोधन करने की अनुमित देते हुए निर्वाचन जारी रखने की अनुमित दे दी है ;

और अब, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित 9.6.2004 के उक्त आदेश के अनुसार और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 153 के साथ पठित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए और साधारण खण्ड अधिनियम 1897(1897 का 10) की धारा 21 और इसकी ओर से इसे सक्षम बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों द्वारा यह निदेश देता है कि निर्वाचन प्रकिया पुनः शुरू की जाए और कि 4 जून, 2004 की निर्वाचन आयोग की अधिसूचना निम्न प्रकार से संशोधित की जाएगी;

खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) और (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगें :

(क)नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख –	17 जून , 2004 (बृहस्पतिवार)
(ख)नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख –	18 जून , 2004 (शुकवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख-	21 जून , 2004 (सोमवार)
(घ)वह तारीख , जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, –	28 जून , 2004 (सोमवार)
(ङ)वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	30 जून , 2004 (बुधवार)
(+) 12	

[सं. 100/रा.स.-म.प्र./1/2004(1)]

आदेश से,

ए.के. मजुमदार, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2004

O.N. 167(E).— Whereas, in pursuance of section 147, sub-section (1) of section 39 and section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India vide its Notification No. 100/CS-MP/1/2004 (1) dated 4th June 2004 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 4th June 2004, pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Madhya Pradesh to elect a person to fill the seat in the Council of States, vacated by Shri Kailashchandra on his election to the House of the People, had appointed:-

- (a) the 11th June, 2004 (Friday), as the last date for making nominations;
- (b) the 12th June, 2004 (Saturday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- (c) the 14th June, 2004 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 21st June, 2004 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 23rd June, 2004 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court by its interim order dated 4th June 2004 on W.P. (C) No. 217 of 2004, was pleased to stay the Notification until further orders and while adding the Election Commission as a party permitted it to move the Hon'ble Court for modification of its interim order;

And whereas, pursuant to the order dated 4th June 2004 of the Hon'ble Supreme Court staying the Notification, the Election Commission had instructed the Returning Officers not to accept nomination papers till further orders;

And whereas, the Election Commission on 5.6.2004 filed an application being I.A. No. 3 in W.P. (C) 217/2004, before the Hon'ble Supreme Court seeking vacation of the stay granted on 4.6.2004 and prayed that the biennial elections to the Rajya Sabha be completed as per schedule;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court in its order dated 9th June 2004 was pleased to dispose of I.A. No. 3 by vacating the stay and permitting the Election Commission to revise the election schedule, if necessary, and proceed with the election;

Now, therefore, the Election Commission pursuant to the above order dated 9.6.2004 passed by the Hon'ble Supreme Court and in exercise of the powers conferred on it by Article 324 of the Constitution of India, read with sub-section (1) of Section 39 and 153 of the Representation of the People Act, 1951, Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and all other powers enabling it in this behalf hereby directs that the election process shall be resumed and that Election Commission Notification dated 4th June 2004 shall be amended as follows:

For clauses (a), (b), (c), (d) and (e), the following clauses shall be substituted:

- (a) the 17th June, 2004 (Thursday), as the last date for making nominations;
- (b) the 18th June, 2004 (Friday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- (c) the 21st June, 2004 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 28th June, 2004 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 30th June, 2004 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed;

No. 100/CS-MP/1/2004(1)]

By Order,

A. K. MAJUMDAR, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2004

आ.अ. 168(अ).— -यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 147 और धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग ने, 4 जून, 2004 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अपनी तारीख 4 जून, 2004 की अधिसूचना सं0 100/रा०स0- उड़ीसा/1/2004(1) द्वारा उड़ीसा राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा की थी कि वे श्री मनमोहन सामल के त्यागपत्र दिये जाने के कारण राज्य सभा में रिक्त हुए स्थान को भरने के लिए एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें;

(क)नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख —	11 जून , 2004	
(ख)नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख -	12 जून , 2004	(शनिवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख-	14 जून , 2004	(सोमवार)
(ग) अभ्याथताए वापस लग का जातन ताराज	21 जून , 2004	
(घ)वह तारीख , जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, और	23 जून , 2004	
(इ)वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा	23 V(1 , 2004	(3-1-11.)
नियत किया था; और		

और यतः, माननीय उच्चतम न्यायालय ने डबल्यू पी. (सी.) सं० 2004 का 217 पर तारीख 4 जून, 2004 के अपने अन्तरिम आदेश द्वारा अगले आदेशों तक अधिसूचना पर रोक लगा दी थी और इसके साथ—'साथ माननीय न्यायालय ने अपने अन्तरिम आदेश में संशोधन के लिए निर्वाचन आयोग को एक पार्टी के रूप में न्यायालय के समक्ष जाने की अनुमति दे दी है ;

और यतः, माननीय उच्चतम न्यायायल ने 4 जून, 2004 के आदेश के द्वारा अधिसूचना पर लगायी गई रोक के मददे नजर, निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग आफिसरों को यह अनुदेश दिए थे कि अगले आदेश होने तक वे नामनिर्देशन पत्र स्वीकार न करें;

और यतः, निर्वाचन आयोग ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष डबल्यू पी. (सी.) 217/2004 में आई. ए. सं० 3 के तहत 4.6.2004 को लगाई गई रोक हटाने के लिए 5.6.2004 को एक आवेदन दाखिल किया था और राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन, कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने का अनुरोध किया था ;

और यतः, माननीय उच्चतम न्यायालय ने 9 जून, 2004 के अपने आदेश द्वारा रोक को खारिज करते हुए आई. ए. सं0 3 का निपटान कर दिया और यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन आयोग को निर्वाचन कार्यकम में संशोधन करने की अनुमित देते हुए निर्वाचन जारी रखने की अनुमित दे दी है ;

और अब, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित 9.6.2004 के उक्त आदेश के अनुसार और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 153 के साथ पठित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए और साधारण खण्ड अधिनियम 1897(1897 का 10) की धारा 21 और इसकी ओर से इसे सक्षम बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों द्वारा यह निदेश देता है कि निर्वाचन प्रकिया पुनः शुरू की जाए और कि 4 जून, 2004 की निर्वाचन आयोग की अधिसूचना निम्न प्रकार से संशोधित की जाएगी ;

खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) और (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगें :

	•
(क)नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख —	17 जून , 2004 (बृहस्पतिवार)
(ख)नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख —	18 जून , 2004 (शुकवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख—	21 जून , 2004 (सोमवार)
(घ)वह तारीख , जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, –	28 जून , 2004 (सोमवार)
(ड़)वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	30 जून , 2004 (बुधवार)

[सं. 100/रा.स.-उड़ीसा/1/2004(1)] आदेश से,

ए.के. मजुमदार, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2004

O.N. 168(E).— Whereas, in pursuance of section 147, sub-section (1) of section 39 and section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India vide its Notification No. 100/CS-OR/1/2004 (1) dated 4th June 2004 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 4th June 2004, pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Orissa to elect a person to fill the seat in the Council of States, vacated by Shri Manamohan Samal by reason of his resignation, had appointed:-

- (a) the 11th June, 2004 (Friday), as the last date for making nominations;
- (b) the 12th June, 2004 (Saturday), as the date for the scrutiny of the nominations;
 - (c) the 14th June, 2004 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - (d) the 21st June, 2004 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
 - (e) the 23rd June, 2004 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court by its interim order dated 4th June 2004 on W.P. (C) No. 217 of 2004, was pleased to stay the Notification until further orders and while adding the Election Commission as a party permitted it to move the Hon'ble Court for modification of its interim order;

And whereas, pursuant to the order dated 4th June 2004 of the Hon'ble Supreme Court staying the Notification, the Election Commission had instructed the Returning Officers not to accept nomination papers till further orders;

And whereas, the Election Commission on 5.6.2004 filed an application being I.A. No. 3 in W.P. (C) 217/2004, before the Hon'ble Supreme Court seeking vacation of the stay granted on 4.6.2004 and prayed that the biennial elections to the Rajya Sabha be completed as per schedule;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court in its order dated 9th June 2004 was pleased to dispose of I.A. No. 3 by vacating the stay and permitting the Election Commission to revise the election schedule, if necessary, and proceed with the election;

Now, therefore, the Election Commission pursuant to the above order dated 9.6.2004 passed by the Hon'ble Supreme Court and in exercise of the powers conferred on it by Article 324 of the Constitution of India, read with sub-section (1) of Section 39 and 153 of the Representation of the People Act, 1951, Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and all other powers enabling it in this behalf hereby directs that the election process shall be resumed and that Election Commission Notification dated 4th June 2004 shall be amended as follows:

For clauses (a), (b), (c), (d) and (e), the following clauses shall be substituted:

- (a) the 17th June, 2004 (Thursday), as the last date for making nominations;
- (b) the 18th June, 2004 (Friday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- (c) the 21st June, 2004 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 28th June, 2004 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 30th June, 2004 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed;

[No. 100/CS-OR/1/2004(1)] By Order, A. K. MAJUMDAR, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2004

आ.अ. 169(अ).— यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 147 और धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग ने, 4 जून, 2004 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अपनी तारीख 4 जून, 2004 की अधिसूचना सं0 100/रा0स0—पंजाब/1/2004(1) द्वारा पंजाब राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा की है कि वे श्री गुरूचरण सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण राज्य सभा में रिक्त हुए स्थान को भरने के लिए एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें :

(क)नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख -	11 जून , 2004	
(ख)नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख -	12 जून , 2004	(शनिवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख-	14 जून , 2004	(सोमवार)
(घ)वह तारीख , जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, और	21 जून , 2004	(सोमवार)
(ड)वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा	23 जून , 2004	(बुधवार)

नियत किया था: और

और यतः, माननीय उच्चतम न्यायालय ने डबल्यू पी. (सी.) सं० 2004 का 217 पर तारीख 4 जून, 2004 के अपने अन्तरिम आदेश द्वारा अगले आदेशों तक अधिसूचना पर रोक लगा दी थी और इसके साथ—साथ माननीय न्यायालय ने अपने अन्तरिम आदेश में संशोधन के लिए निर्वाचन आयोग को एक पार्टी के रूप में न्यायालय के समक्ष जाने की अनुमति दे दी है;

और यतः, माननीय उच्चतम न्यायायल ने 4 जून, 2004 के आदेश के द्वारा अधिसूचना पर लगायी गई रोक के मददे नजर, निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग आफिसरों को यह अनुदेश दिए थे कि अगले आदेश होने तक वे नामनिर्देशन पत्र स्वीकार न करें;

और यतः, निर्वाचन आयोग ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष डबल्यू पी. (सी.) 217/2004 में आई. ए. संठ 3 के तहत 4.6.2004 को लगाई गई रोक हटाने के लिए 5.6.2004 को एक आवेदन दाखिल किया था और राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन, कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने का अनुरोध किया था ;

और यतः,माननीय उच्चतम न्यायालय ने 9 जून, 2004 के अपने आदेश द्वारा रोक को खारिज करते हुए आई. ए. सं० 3 का निपटान कर दिया और यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन आयोग को निर्वाचन कार्यकम में संशोधन करने की अनुमति देते हुए निर्वाचन जारी रखने की अनुमति दे दी है ;

और अब, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित 9.6.2004 के उक्त आदेश के अनुसार और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 153 के साथ पठित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए और साधारण खण्ड अधिनियम 1897(1897 का 10) की धारा 21 और इसकी ओर से इसे सक्षम बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों द्वारा यह निर्देश देता है कि निर्वाचन प्रकिया पुनः शुरू की जाए और कि 4 जून, 2004 की निर्वाचन आयोग की अधिसूचना निम्न प्रकार से संशोधित की जाएगी ;

खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) और (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगें :

(क)नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख –	17 जून , 2004 (बृहस्पतिवार)
(ख)नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख –	18 जून , 2004 (शुक वार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख—	21 जून , 2004 (सोमवार)
(घ)वह तारीख , जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, —	28 जून , 2004 (सोमवार)
(ड़)वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	30 जून , 2004 (बुधवार)

[सं. 100/रा.स.-पंजाब/1/2004(1)]

आदेश से,

ए.के. मजुमदार, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2004

O.N. 169(E).— Whereas, in pursuance of section 147, sub-section (1) of section 39 and section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India vide its Notification No. 100/CS-PB/1/2004 (1) dated 4th June 2004 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 4th June 2004, pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Punjab to elect a person to fill the seat in the Council of States, caused by the death of Shri Gurcharan Singh, had appointed:-

- (a) the 11th June, 2004 (Friday), as the last date for making nominations;
- (b) the 12th June, 2004 (Saturday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- (c) the 14th June, 2004 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 21st June, 2004 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 23rd June, 2004 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court by its interim order dated 4th June 2004 on W.P. (C) No. 217 of 2004, was pleased to stay the Notification until further orders and while adding the Election Commission as a party permitted it to move the Hon'ble Court for modification of its interim order;

And whereas, pursuant to the order dated 4th June 2004 of the Hon'ble Supreme Court staying the Notification, the Election Commission had instructed the Returning Officers not to accept nomination papers till further orders;

And whereas, the Election Commission on 5.6.2004 filed an application being I.A. No. 3 in W.P. (C) 217/2004, before the Hon'ble Supreme Court seeking vacation of the stay granted on 4.6.2004 and prayed that the biennial elections to the Rajya Sabha be completed as per schedule;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court in its order dated 9th June 2004 was pleased to dispose of I.A. No. 3 by vacating the stay and permitting the Election Commission to revise the election schedule, if necessary, and proceed with the election;

Now, therefore, the Election Commission pursuant to the above order dated 9.6.2004 passed by the Hon'ble Supreme Court and in exercise of the powers conferred on it by Article 324 of the Constitution of India, read with sub-section (1) of Section 39 and 153 of the Representation of the People Act, 1951, Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and all other powers enabling it in this behalf hereby directs that the election process shall be resumed and that Election Commission Notification dated 4th June 2004 shall be amended as follows:



For clauses (a), (b), (c), (d) and (e), the following clauses shall be substituted:

- (a) the 17th June, 2004 (Thursday), as the last date for making nominations;
- (b) the 18th June, 2004 (Friday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- (c) the 21st June, 2004 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 28th June, 2004 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 30th June, 2004 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed;

[No. 100/CS-PB/1/2004(1)] By Order, A. K. MAJUMDAR, Secv.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2004

आ.अ. 170(अ).—यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 147 और धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग ने, 4 जून, 2004 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अपनी तारीख 4 जून, 2004 की अधिसूचना सं0 100/रा0स0-राज0/2/2004(1) द्वारा राजस्थान राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा की थी कि वे डां अबरार अहमद की मृत्यु हो जाने के कारण राज्य सभा में रिक्त हुए स्थान को भरने के लिए एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें;

(क)नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख –	11 जून , 2004	(शुकवार)
(ख)नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख —	12 जून , 2004	(शनिवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख—	14 जून , 2004	(सोमवार)
(घ)वह तारीख , जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, और	21 जून , 2004	(सोमवार)
(ड़)वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा	23 जून , 2004	(बुधवार)
नियत किया था; और	•	

और यतः, माननीय उच्चतम न्यायालय ने डबल्यू पी. (सी.) संठ 2004 का 217 पर तारीख 4 जून, 2004 के अपने अन्तरिम आदेश द्वारा अगले आदेशों तक अधिसूचना पर रोक लगा दी थी और इसके साथ—'साथ माननीय न्यायालय ने अपने अन्तरिम आदेश में संशोधन के लिए निर्वाचन आयोग को एक पार्टी के रूप में न्यायालय के समक्ष जाने की अनुमति दे दी है ;

और यतः, माननीय उच्चतम न्यायायल ने 4 जून, 2004 के आदेश के द्वारा अधिसूचना पर लगायी गई रोक के मददे नजर, निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग आफिसरों को यह अनुदेश दिए थे कि अगले आदेश होने तक वे नामनिर्देशन पत्र स्वीकार न करें ;

और यतः, निर्वाचन आयोग् ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष डबल्यू पी. (सी.) 217/2004 में आई. ए. संठ 3 के तहत 4.6.2004 को लगाई गई रोक हटाने के लिए 5.6.2004 को एक आवेदन दाखिल किया था और राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन, कार्यकम के अनुसार पूरा करने का अनुरोध किया था ;

और यतः, माननीय उच्चतमं न्यायालय ने 9 जून, 2004 के अपने आदेश द्वारा रोक को खारिज करते हुए आई. ए. सं0 3 का निपटान कर दिया और यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन आयोग को निर्वाचन कार्यक्रम में संशोधन करने की अनुमति देते हुए निर्वाचन जारी रखने की अनुमति दे दी है ; और अब, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित 9.6.2004 के उक्त आदेश के अनुसार और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 153 के साथ पठित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए और साधारण खण्ड अधिनियम 1897(1897 का 10) की धारा 21 और इसकी ओर से इसे सक्षम बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों द्वारा यह निदेश देता है कि निर्वाचन प्रक्रिया पुनः शुरू की जाए और कि 4 जून, 2004 की निर्वाचन आयोग की अधिसूचना निम्न प्रकार से संशोधित की जाएगी ;

खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ.) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगें :

(क)नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख —	17 जून , 2004 (बृहस्पतिवार)
(ख)नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख –	18 जून , 2004 (शुकवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख—	21 जून , 2004 (सोमवार)
(घ)वह तारीख , जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, -	28 जून , 2004 (सोमवार)
(ड़)वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	30 जून , 2004 (बु घवार)

[सं. 100/रा.स.-राज./2/2004(1)]

आदेश से,

ए.के. मजुमदार, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2004

O.N. 170(E).— Whereas, in pursuance of section 147, sub-section (1) of section 39 and section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India vide its Notification No. 100/CS-RJ/2/2004 (1) dated 4th June 2004 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 4th June 2004, pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Rajasthan to elect a person to fill the seat in the Council of States, caused by the death of Dr. Abrar Ahmed, had appointed:-

- (a) the 11th June, 2004 (Friday), as the last date for making nominations;
- (b) the 12th June, 2004 (Saturday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- (c) the 14th June, 2004 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 21st June, 2004 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 23rd June, 2004 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court by its interim order dated 4th June 2004 on W.P. (C) No. 217 of 2004, was pleased to stay the Notification until further orders and while adding the Election Commission as a party permitted it to move the Hon'ble Court for modification of its interim order;

And whereas, pursuant to the order dated 4th June 2004 of the Hon'ble Supreme Court staying the Notification, the Election Commission had instructed the Returning Officers not to accept nomination papers till further orders;

And whereas, the Election Commission on 5.6.2004 filed an application being I.A. No. 3 in W.P. (C) 217/2004, before the Hon'ble Supreme Court seeking vacation of the stay granted on 4.6.2004 and prayed that the biennial elections to the Rajya Sabha be completed as per schedule;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court in its order dated 9th June 2004 was pleased to dispose of I.A. No. 3 by vacating the stay and permitting the Election Commission to revise the election schedule, if necessary, and proceed with the election;

Now, therefore, the Election Commission pursuant to the above order dated 9.6.2004 passed by the Hon'ble Supreme Court and in exercise of the powers conferred on it by Article 324 of the Constitution of India, read with sub-section (1) of Section 39 and 153 of the Representation of the People Act, 1951, Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and all other powers enabling it in this behalf hereby directs that the election process shall be resumed and that Election Commission Notification dated 4th June 2004 shall be amended as follows:

For clauses (a), (b), (c), (d) and (e), the following clauses shall be substituted:

- (a) the 17th June, 2004 (Thursday), as the last date for making nominations;
- (b) the 18th June, 2004 (Friday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- (c) the 21st June, 2004 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 28th June, 2004 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 30th June, 2004 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed;

[No. 100/CS-RJ/2/2004(1)] By Order, A. K. MAJUMDAR, Secy.

अधिसचना

नई दिल्ली, 10 जुन, 2004

आ.अ. 171(अ).— यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 147 और धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग ने, 4 जून, 2004 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अपनी तारीख 4 जून, 2004 की अधिसूचना सं0 100/रा0स0—प0 बं0/1/2004(1) द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा की थी कि वे लोकसभा के लिए श्री प्रवण मुखर्जी के निर्वाचित होने के कारण राज्य सभा में रिक्त हुए स्थान को भरने के लिए एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें :

(क)नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख —	11 जून , 2004	
(ख)नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख -	12 जून , 2004	(शनिवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख-	14 जून , 2004	(सोमवार)
(घ)वह तारीख , जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, और	21 जून , 2004	(सोमवार)
(इ)वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा	ू 23 जून , 2004	
	& .	\
नियत किया था; और		

और यतः, माननीय उच्चतम न्यायालय ने डबल्यू पी. (सी.) सं० 2004 का 217 पर तारीख 4 जून, 2004 के अपने अन्तरिम आदेश द्वारा अगले आदेशों तक अधिसूचना पर रोक लगा दी थी और इसके साथ—'साथ माननीय न्यायालय ने अपने अन्तरिम आदेश में संशोधन के लिए निर्वाचन आयोग को एक पार्टी के रूप में न्यायालय के समक्ष जाने की अनुमति दे दी है;

और यतः, माननीय उच्चतम न्यायायल ने 4 जून, 2004 के आदेश क़े द्वारा अधिसूचना पर लगायी गई रोक के मददे नजर, निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग आफिसरों को यह अनुदेश दिए थे कि अगले आदेश होने तक वे नामनिर्देशन पत्र स्वीकार न करें ;

और यतः, निर्वाचन आयोग ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष डबल्यू पी. (सी.) 217/2004 में आई. ए. संठ 3 के तहत 4.6.2004 को लगाई गई रोक हटाने के लिए 5.6.2004 को एक आवेदन दाखिल किया था और राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन, कार्यकम के अनुसार पूरा करने का अनुरोध किया था ;

और यतः, माननीय उच्चतम न्यायालय ने 9 जून, 2004 के अपने आदेश द्वारा रोक को खारिज करते हुए आई. ए. सं0 3 का निपटान कर दिया और यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन आयोग को निर्वाचन कार्यक्रम में संशोधन करने की अनुमति देते हुए निर्वाचन जारी रखने की अनुमति दे दी है ;

और अब, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित 9.6.2004 के उक्त आदेश के अनुसार और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 153 के साथ पठित भारतीय संविधान के अनुस्केद 324 द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए और साधारण खण्ड अधिनियम 1897(1897 का 10) की धारा 21 और इसकी ओर से इसे सक्षम बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों द्वारा यह निदेश देता है कि निर्वाचन प्रकिया पुनः शुरू की जाए और कि 4 जून, 2004 की निर्वाचन आयोग की अधिसूचना निम्न प्रकार से संशोधित की जाएगी ;

खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) और (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगें :

(क)नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख —	17 जून , 2004 (बृहस्पतिवार)	
(ख)नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख –	18 जून , 2004 (शुक् वार)	
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख-	21 जून , 2004 (सोमवार)	
(घ)वह तारीख , जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, —	28 जून , 2004 (सोमवार)	
(इ)वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	30 जून , 2004 (बुधवार)	

[सं. 100/रा.स.-प.बं./1/2004(1)]

आदेश से,

ए.के. मजुमदार, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2004

O.N. 171(E).— Whereas, in pursuance of section 147, sub-section (1) of section 39 and section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India vide its Notification No. 100/CS-WB/1/2004 (1) dated 4th June 2004 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 4th June 2004, pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of West Bengal to elect a person to fill the seat in the Council of States, vacated by Shri Pranab Mukherjee on his election to the House of the People, had appointed:-

1801 affor

- (a) the 11th June, 2004 (Friday), as the last date for making nominations;
- (b) the 12th June, 2004 (Saturday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- (c) the 14th June, 2004 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 21st June, 2004 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 23rd June, 2004 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court by its interim order dated 4th June 2004 on W.P. (C) No. 217 of 2004, was pleased to stay the Notification until further orders and while adding the Election Commission as a party permitted it to move the Hon'ble Court for modification of its interim order;

And whereas, pursuant to the order dated 4th June 2004 of the Hon'ble Supreme Court staying the Notification, the Election Commission had instructed the Returning Officers not to accept nomination papers till further orders;

And whereas, the Election Commission on 5.6.2004 filed an application being I.A. No. 3 in W.P. (C) 217/2004, before the Hon'ble Supreme Court seeking vacation of the stay granted on 4.6.2004 and prayed that the biennial elections to the Rajya Sabha be completed as per schedule;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court in its order dated 9th June 2004 was pleased to dispose of I.A. No. 3 by vacating the stay and permitting the Election Commission to revise the election schedule, if necessary, and proceed with the election;

Now, therefore, the Election Commission pursuant to the above order dated 9.6.2004 passed by the Hon'ble Supreme Court and in exercise of the powers conferred on it by Article 324 of the Constitution of India, read with sub-section (1) of Section 39 and 153 of the Representation of the People Act, 1951, Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and all other powers enabling it in this behalf hereby directs that the election process shall be resumed and that Election Commission Notification dated 4th June 2004 shall be amended as follows:

For clauses (a), (b), (c), (d) and (e), the following clauses shall be substituted:

- (a) the 17th June, 2004 (Thursday), as the last date for making nominations;
- (b) the 18th June, 2004 (Friday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- (c) the 21st June, 2004 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 28th June, 2004 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 30th June, 2004 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed;

[No. 100/CS-WB/1/2004(1)]

By Order,

A. K. MAJUMDAR, Secy.